



## अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती रूपए की ताकत एवं भारत में बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार

(लेखक-प्रह्लाद सबनानी

दिनांक 7 फरवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत सबसे निचले स्तर 87.44 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई थी। इसके बाद धीरे धीरे इसमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया है एवं अब दिनांक 30 अप्रैल 2025 को यह 84.50 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं दिनांक 18 अप्रैल 2025 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ 68,610 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है और यह दिनांक 27 सितम्बर 2024 के उच्चतम स्तर 70,489 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर के बहुत करीब है। भारतीय रुपए की मजबूती एवं विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब विश्व के समस्त देश अमेरिकी प्रशासन के टैरिफ युद्ध का सामना करते हुए संकट में दिखाई दे रहे हैं। परंतु, भारत पर टैरिफ युद्ध का असर लगभग नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है। यह भी सही है कि हाल ही के समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ा है और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगभग 109 के स्तर से नीचे गिरकर दिनांक 30 अप्रैल 2025 को 99.43 के स्तर पर आ गया है। शायद अमेरिका भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को कम करना चाहता है ताकि अमेरिका में आयात महगे हों एवं अमेरिकी निर्यातिकों को अधिक लाभ पहुंचे। परंतु, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर पर दबाव के बढ़ने से सोने की कीमतों में अतुलनीय वृद्धि दर्ज हुई है और यह दिनांक 22 अप्रैल 2025 को अपने उच्चतम स्तर 3500 अमेरिकी डॉलर प्रति आउन्स पर पहुंच गई थी। साथ ही, अमेरिकी शेयर बाजार भी धराशायी हुआ है और डाइ जॉस एवं अन्य इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज हुई है। अब ऐसा आभास हो रहा है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध छेड़ गए टैरिफ युद्ध का विपरीत असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।

अपना निवेश बढ़ाने लगे हैं एवं पिछले लगातार 8 दिनों से इन विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में शेयरों की भारी मात्रा में खरीद की है। जबकि, सितम्बर 2024 के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार अपना निवेश निकाल रहे थे और इस विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री भारतीय शेयर बाजार में की है। जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार के निपटी इंडेक्स में लगभग 3500 अंकों की भारी गिरावट दर्ज हुई थी। परंतु, भारतीय संस्थागत निवेशकों, भारतीय म्यूच्युअल फण्ड एवं खुदरा निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में अपना निवेश बढ़ाकर भारतीय पूँजी बाजार को सम्मालने में मदद की है अन्यथा भारतीय शेयर बाजार क्रेश हो गया होता। परंतु, अब भारतीय शेयर बाजार में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है एवं अब एक बार पुनः यह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही के समय में निपटी इंडेक्स में लगभग 1500 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है।

टनाओं के परिणाम वरूप अंतरराष्ट्रीय जार में भारतीय रुपए दबाव कुछ कम होता आ दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोष रूप से आर्थिक त्र में भले स्थितियाँ क नहीं दिखाई दे रही , परंतु भारत में अंतरिक मजबूती के लते भारतीय व्यवस्था अभी भी इश्क की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज व्यवस्था बनी हुई है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई फ



गति से आगे बढ़ती हुई रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, वेकास बैंक, स्टैंडर्ड एवं स्थानों ने भी वित्तीय वर्ष पर अर्थिक क्षेत्र में देशों के बीच भी, भारतीय बैंक की दर से आगे बढ़ने योरोप के कुछ देशों यथा अमेरिका में मंदी की रही है। अमेरिका में तो नवरी-मार्च 2025) में गत की गिरावट दर्ज हुई देशों तथा जापान आदि भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से आगे बढ़ने के पीछे भारत की आंतरिक मजबूती मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही है। भारत में अभी हाल ही में महाकुम्भ मेला सम्पन्न हुआ है, इस महाकुम्भ में लगभग 66 करोड़ भारतीय मूल के नागरिकों ने पवित्र त्रिवेणी में आरथा की दुक्की लगाई। इतनी भारी मात्रा में नागरिकों के यहां पहुंचने से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल ही मिल है। महाकुम्भ में भाग ले रहे प्रत्येक नागरिक ने औसत रूप से यदि 2000 रुपए भी प्रतिदिन खर्च किए हों और प्रत्येक नागरिक ने औसतन कुल तीन दिवस भी महाकुम्भ में बिताए हों तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 396,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ पहुंचा है।

दर में भी गिरावट आती लापान एवं जर्मनी की 2026 में गिरावट दर्ज 6 प्रतिशत की विकास अभव है कि वर्ष 2025 में जो पीछे छोड़ते हुए भारत बाद तीसरे नम्बर की परिस्थितियों के बीच भी रहा है। आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया गया जिसका लाभ आने वाले कई वर्षों तक देश को मिलता रहेगा। देश में धार्मिक पर्यटन भी भारी मात्रा में बढ़ा है जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। धार्मिक पर्यटन एवं महाकृष्ण के चलते ही अब यह आंकलन हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हो सकती है।

www.mechanics.tutorialspoint.com

संपादकीय

जाते जनगणना

लवे समय तक असहमति के बाद आखिरकार भाजपा नेतृत्व वालों राजग सरकार ने घोषणा कर दी है कि जाति गणना अगली जनगणना का हिस्सा होगी। बहरहाल, भाजपा ने विपक्ष के जातीय गणना के मुद्दे की हवा निकाल दी है। यह आशुर्यजनक निर्णय विषम परिस्थितियों के बीच आया है जब देश को उम्मीद थी कि सरकार पहलगाम हमते के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि, भाजपा ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित चुनावी प्राथमिकताओं से प्रभावित नहीं होंगे। निससंदेह, राजग का अल्पकालिक लक्ष्य इस साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतना है। वहीं बड़ा उद्देश्य देशभर में जाति के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य प्रतिद्वंद्वी दलों को पछाड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में यह कहकर चीजों को सरल बनाने की कोशिश की थी कि देश में चार ही जातियां हैं—महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। यहीं वजह है कि धृतीकरण की अपनी ताकत के प्रति आश्वस्त भगवा पार्टी ने विपक्ष को जाति का कार्ड खेलने दिया। हालांकि, इसका झटका भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा। ये परिणाम भाजपा के लिये आंख खोलने वाला था। हालांकि, वह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल युनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के सहयोग से किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब हो गई। इस बात में कोई आश्वर्य नहीं होना चाहिए कि गठबंधन की मजबूरियों के चलते ही भाजपा को जाति जनगणना के मुद्दे पर यह फेसला लेना पड़ा है। हालांकि, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के दबाव ने भी इस निर्णय में बड़ी भूमिका निभाई है। एक अन्य प्रमुख खारण भी मराव अंवेदकर की विरासत को लेकर खीचतान भी है। कोई भी राजनीतिक दल सामाजिक न्याय के उनके महान सपने को पूरा करने के लिये आधे-अधूरे दृष्टिकोण को अपनाने का जोखिम नहीं उठा सकता, खासकर भाजपा। कहा जा रहा है कि जाति जनगणना के जरिये नीति निर्माताओं को विशिष्ट समुदायों की आवश्यकता के अनुसार कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। इसमें दो राय नहीं कि जाति आधारित जनगणना में पारदर्शी सूचनाओं के संग्रह और डेटा के सार्थक उपयोग से सामाजिक असमानताओं को दूर करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इसके लिये समय सीमा तय की जाए, दर्योंकि पहले ही जनगणना में काफी देरी हो चुकी है। यह भी हकीकत है कि केंद्र सरकार के लिये अगली जनगणना के साथ ही जाति गणना कराने का फैसला खासा चुनौतीपूर्ण है। जिसके गहरे निहितार्थ सामने आ सकते हैं, जो राजनीतिक व सामाजिक परिवृश्य में बदलावकारी प्रभाव छोड़ सकते हैं। बहुत संभव है कि इसके बाद आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग भी जार पकड़े। लेकिन प्रथम दृष्ट्या भाजपा विपक्ष के बड़े हथियार को हथियाने में सफल रही है। उल्लेखनीय है कि साल 1931 तक ही जनगणना में जाति गणना भी शामिल रही है, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसकी आवश्यकता को नकार दिया गया। हालांकि, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना की जाती रही। वैसे साल 2011 में सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों के लिये जाति गणना की तो जरूर गई, लेकिन विसंगतियों के चलते आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। जबकि पिछले कुछ समय से विपक्ष आरक्षण को तार्किक बनाने के लिये जाति गणना की वकालत करता रहा है। हालांकि, पहले भाजपा भारतीय समाज के हित में जाति गणना के प्रस्ताव को आपासिक बताती रही है, लेकिन देश के राजनीतिक परिवृश्य में विपक्ष द्वारा इसे बड़ा मुद्दा बनाने के बाद

(लेखक- लित गर्ग )  
करने के लिए सर्व कराए, योंकि जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को ही है। हालांकि भाजपा ने बिहार में जाति आधारित सर्व कदम हो सकता है। जनगणना में दलितों और आर्थिक तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षणीय दलित शिवारी और अर्थशिवारी / अर्थशिवी भी कहा जाता है।

( लखफ- लालत गग )

पहलानाम का झूर एवं बवर आतका घटना के बाद मादा सरकार लगातार पाकिस्तान को करारा जबाव देने की तैयारी के अति जटिल एवं संवेदनशील दौर में एकाएक जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लेकर न विपक्षी दलों को बल्कि समृद्ध देश को चौकाया एवं चमत्कृत किया है। सरकार का यह निर्णय जितना बड़ा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। मोदी सरकार का जातिगत जनगणना के लिए तैयार होना सुख और स्वागतयोग्य है। पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना की मांग बहुत जोर-शोर से हो रही थी। कुछ राज्यों में तो भाजपा भी ऐसे जनगणना के पक्ष में दिखी थी, पर केंद्र सरकार का रुख इस पर बहुत साफ नहीं हो रहा था। अब अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति व थैठर में यह फैसला ले लिया गया। बाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी धैर्या ने मीडिया को बताया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना १० शामिल रहेगी। यह कदम जहां देश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को बदलेगा, वही सामाजिक असमानताओं को दूर कर और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू कर में मील का पथर साबित होगा।

ज्ञातिगत जनगणना 1931 वाना अखड़ भारत में अंग्रेजा से तो कराई थी। भारत में जनगणना की शुरूआत अंग्रेजी हुक्मूमत के दौर में सन 1872 में हुई थी और 1931 तक हुई हर जनगणना में जाति व जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी के बाद सन 1951 जब पहली बार जनगणना कराई गई, तो तय हुआ कि अब जाति से जुआंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे। स्वतंत्र भारत में हुई जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े डेटा को ही पब्लिश किया गया। 2011 में मनमोहन सरकार ने जातिवार जनगणना कराई अवश्य लेकिन उसमें इन्हीं जटिलताएं एवं विसंगतियां मिलीं कि उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद कुछ राज्यों ने जातियों की गिनती

करन का लिए सब कराए, व्याक जनगणना करन का आधकार कर केंद्र को ही है। हालांकि भाजपा ने बिहार में जाति आधारित सर्वे का समर्थन किया, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर वह मुखर न रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अवश्य इसका समर्थन किया। लेकिन अब एकाएक भाजपा को जातिगत जनगणना करना अपने हित दिखाई दिया व्याक अपनी नीतियों एवं योजनाओं के बल पर भाजपा पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान बनाया है। जातिगत जनगणना का भारतीय राजनीति और समाज व्यवस्था पर व्यापक एवं दूरगमी प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल इसकी पुरजोर मांग करने में लगे हुए थे। सबसे ज्यादा जोर राहगांधी दे रहे थे, जबकि नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक ने इसकी जरूरत नहीं समझी। यह तथ्य है कि जातिगत जनगणना कराने कैसले पर जहां कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल इसका श्रेय लेना वाहां वहीं भाजपा इसे सामाजिक न्याय एवं समता-संतुलित समाज-निमित्त केंद्रित अपनी पहल बताएगी। जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय में सहायक बनेगी या नहीं, लेकिन इससे जातिवादी राजनीति नए दरवाजे खुलेंगे एवं आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति की धूरी बनेगा। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों ने अपने सकीर्ण एवं स्वामी राजनीतिक नजरिये से यह मांग इसलिए उठाई थी ताकि इस आधार पर आगे आरक्षण के मुद्दे को गर्माया जा सके और जातीय गोलबंदी को चुनावी फायदा लिया जा सके। लेकिन भाजपा-सरकार ने जातिगणना का ऐलान कर इस मुद्दे को अपनी पाली में ले लिया है। इसके आंकड़े आने के बाद आवादी के अनुपात में आरक्षण की मात्रा से भाजपा कैसे निपटेगी, यह बड़ी चुनौती उसके सामने है। वैसे भी इस तरह की पहल जिन राज्यों में हुई है, वहां भी इसे लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे विवाद भाजपा के लिये एक नयी चुनौती बनेंगे। जाति आधारित जनगणना से भारतीय समाज के नये कोने-अंतरे-चुनौतियां सामने आयेंगी। लेकिन जातिगत जनगणना के समर्थकों का मानना है कि इस सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिक

कदम हा सकता ह। जनगणना म दालता आर आदवासया का सख्ता तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिला हुआ है लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी (ओबीसी और ईबीसी) जातियों के कितने लोग देश में हैं इसकी गिनती नहीं होती है। जनगणना एक बहुत बड़ी काव्यद है और अगर इसमें जातिगत गणना को भी शामिल किया जा रहा है, तो काम और भी सावधानी एवं सतर्कता से करना होगा। हजारों जातियां हैं और उनकी हजारों उप-जातियां हैं। सबको अलग-अलग गिनने के लिए देश को अपनी डिजिटल शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। निश्चित ही नयी राजनीतिक एवं नीतिगत स्थितियां समस्याएं खड़ी होगी। अब सभी जातियों की गिनती होगी। यह गिनती मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदायों में भी होनी चाहिए, वयोंकि कोई दावा कुछ भी करे, जाति और उसके आधार पर विभेद सब जगह है। इससे भी ज्यादा आवश्यक, बल्कि अनिवार्य यह है कि जातिगत जनगणना जातिवाद की राजनीति का हथियार न बने और वह भारतीय समाज को विभाजित न करने पाए। इस अंदेशों को दूर करने के कुछ ठोस उपाय होने ही चाहिए कि जाति आधारित जनगणना जातीय विभाजन का कारण न बनने पाए। यह अंदेशा इसलिए है, वयोंकि यह किसी से छिपा नहीं कि कई राजनीतिक दल खुले रूप से जाति की राजनीति करते हैं। माना जाता है कि देश की आबादी में 52 फ़ीसदी लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफ़ी कम है। राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। भारत में जाति जनगणना आजादी के बाद रुकी, पर अब सामाजिक न्याय, नीतिगत सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। पारदर्शिता और सावधानी से किया गया यह कदम समावेशी विकास का आधार बन सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति आधारित जनगणना को एक समतामूलक समाज निर्माण के दृष्टिकोण से समर्थन देने के सकेत दिए हैं।

(चिंतन- मनन)



कमंडल के मुकाबले में अब मंडल की राजनीति का समय

(लेखक- सनत जैन )

जनगणना हुई थी उसी समय 4000 जातियां और उपजातियों के आधार पर जनगणना के परिणाम आए थे। 2011 में यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई। 2011 में जनगणना पंजीयक द्वारा सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना पर 4389 क्रोड रुपए खर्च किए गए थे। बड़े पैमाने पर जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से पूरी की गई थी। इस जनगणना में जनगणना कर्मियों ने घर-घर जाकर सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, आय, व्यवसाय, आवास की स्थिति, रहन-सहन का स्तर, बाहन से संबंधित जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनी उपकरण, खेती-किसानी का तौर तरीका और उसमें उपयोग होने वाले उपकरण, परिवार में नौकरी से संबंधित जानकारी, सरकारी सेवा में लोगों की जानकारी, सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी, जातीय तथा उपजाति के आधार पर सारी सुचनाएं एकत्रित की गई थीं। भारत के

640 जिलों में 24 लाख ब्लॉक में यह जनगणना की गई थी। 2011 से यह जनगणना शुरू हुई थी जो 2016 में जाकर पूर्ण हुई थी। 2016 में जब जाति जनगणना के आंकड़े आए तो इसे तत्कालीन मोदी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जनगणना के आंकड़ों से इसे अलग कर दिया गया। 2011 की जनगणना में 40 लाख से अधिक जातियों की पहचान हुई थी। इनको पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी और सामान्य वर्ग में विभाजित करने को लेकर सरकार असमंजस में रही। 2016 में यदि जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होते तो यह देश की राजनीति को बदल सकते थे। इस डर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे उजागर नहीं किया। जातीय जनगणना को लेकर पिछले कुछ वर्षों में विहार, तेलंगाना और कर्नाटक ने अपने तरीके से जातीय सर्वक्षण कराए हैं। उनके आंकड़े भी सामने आए हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था में धर्मिक एवं जाति आधार बहुत मजबूत हैं। भारत दूनिया का सबसे

बड़ा विविधता वाला देश है। यहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा बौलियां हैं, सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, सबसे ज्यादा धर्म जाति आधार पर देखने को मिलते हैं। भारत की एक बड़ी दलित और आदिवासी आबादी अपनी विभिन्न परंपराओं और विभिन्न आस्थाओं के कारण एक अलग पहचान बनाती है। उनकी मान्यताएं भी अलग-अलग होती हैं। 2016 में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने 2016 में एक बार फिर मंडल और कमंडल की लड़ाई को तेज करने की कोशिश की थी। लालू यादव जेल गए, वहां उनका खास्थ खराब हो गया उसके बाद यह मांग कमज़ोर पड़ गई थी। लालू यादव हाते थे कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। मोदी सरकार इससे बचती रही। 2022 के बाद यह मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर एक आंदोलन चलाने की कोशिश की, जो सफल होती ही दिख

है। सरकार को भी 2025 में जनगणना के साथ जाति गणना करने के लिए विवास होना पड़ा है। भारत में अब आबादी जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। अग-अलग राज्यों में जाति समूह के आधार पर जातिक और राजनीतिक व्यवस्था जमीन से जुड़ी हुई विहार विधानसभा चुनाव में जाति जनगणना सर्वेक्षण के थम से एकत्रित की गई थी।

उसके आधार पर बड़े राजनीतिक परिवर्तन की संभावना रूप में देखा जा रहा है। इसी दबाव को देखते हुए तीय जनता पार्टी अभी तक जाति जनगणना का विरोध रही थी, लेकिन उसे भी अब जाति जनगणना के थर्न में आना पड़ा है। मोदी सरकार के इस निर्णय का असर भविष्य की राजनीति में पड़ेगा, इसको लेकर अ-तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। 2014 के बाद से अति वाद ने कई जाति और समूहों के बीच में एक अलगाव स्थिति लाकर खड़ी कर दी है।



